

बांसवाड़ा में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 36.60 वर्गमीटर (393.816 वर्गफीट) है, जिसके पूर्व में अन्य हाउसिंग बोर्ड
पश्चिम में सड़क, उत्तर में मकान सं 1-एफ-23, दक्षिण में मकान सं. 1-एफ-21 है, को बतौर प्रतिभूति
बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात
ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

भारत का राजपत्र क्रमांक 1005 दिनांक 10 नवम्बर 2003 की अधिसूचना के अनुसार प्रार्थी दिवान
हाउसिंग फ़ायनेंस लिमिटेड को केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति
हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की उपधारा(1) के खंड (ड) के उप-खंड (IV) के
अन्तर्गत वित्तीय संस्था घोषित की है। प्रार्थी संस्था द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र
की प्रति संलग्न की है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के
कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) सरफेसी एक्ट 2002 के तहत दिनांक
18-02-2019 को ऋणी अप्रार्थीगणों को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नहीं की
व ऋण राशि जमा नहीं करवाई। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित लोन एग्रीमेन्ट
है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक
06.08.2021 को जारी किये गए। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के नोटिस दिनांक 23.09.2021 को बाद चस्या रिपोर्ट
तहसीलदार बांसवाड़ा के साथ प्रस्तुत हुए। सही एवं पूर्ण पते के अभाव में अप्रार्थी सं. 3 का नोटिस अदम
तामिल रहा है।

अतः नोटिस बाद चस्या होकर प्रस्तुत होने एवं अप्रार्थीगण सं 1 व 2 को समुचित अवसर प्रदान करने
के बावजूद अनुपस्थित रहे हैं। अतः अप्रार्थीगण सं 1 व 2 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती
है। अप्रार्थी सं. 3 जमानती होकर प्रकरण में औपचारिक पक्षकार है। इनको सुना जाना न्यायोचित प्रतित नहीं
होता है।

दिनांक 11.05.2022 को प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता
द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे
है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।



[Handwritten Signature]


कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अक्त सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तीय संस्था का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बॉसवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात दीवान हाउसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय वार्डन हाउस, द्वितीय तल, सर. पी.एम रोड, फोर्ट मुम्बई- 400001 तथा शाखा कार्यालय 302/5 तृतीय तल, बॉसवाड़ा टावर, एम.आई रोड, बॉसवाड़ा, राजस्थान को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।




(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)
बांसवाड़ा